भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 300
(05 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)
तमिलनाडु में पीएमएवाई-जी

300. **श्री सेल्वम जी.:**
श्री धनुष एम. कुमार:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कार्यान्वित की जा रही है;
(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;
(ग) कितने मकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है और कितने मकानों के लिए धनराशि जारी की गई है; और
(घ) तमिलनाडु में उक्त योजना के अंतर्गत पहले से स्वीकृत/स्वीकृत किए जाने वाले मकानों के निर्माण को पूरा करने के लिए निधियां जारी करने हेतु बचे हुए अनुरोधों/आवेदनों को अनुमोदित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कार्यान्वित कर रहा है। मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं वाले 2.95 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। दिनांक 29.11.2023 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लाभार्थियों के लिए 2.94 करोड़ से अधिक आवासों को मंजूरी दी है और 2.50 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा कर लिया है।

इसके अलावा, दिनांक 29.11.2023 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य के लिए लक्षित, स्वीकृत, जारी की गई किस्तों की संख्या और पूरे किए गए आवासों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

लक्ष्य	राज्य द्वारा स्वीकृत आवास	पहली किस्त जारी	दूसरी किस्त जारी	तीसरी किस्त जारी	चौथी किस्त जारी	आवासों का निर्माण पूरा हुआ
7,79,851	7,59,184	7,43,778	6,34,145	5,84,390	5,63,664	5,82,264

(घ): पीएमएवाई-जी के तहत,योजना की शुरुआत से तमिलनाडु राज्य को 5321.64 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। राज्य ने राज्य अंश सहित 7627.08 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया है। इस योजना के राज्य नोडल खाते (एसएनए) में 1247.27 करोड़ रुपए की व्यय न की गई शेष राशि उपलब्ध है। एसएनए में व्यय न की गई शेष राशि काफी अधिक होने और राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के कारण केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई कार्यक्रम निधि जारी नहीं की जा सकी। तमिलनाडु राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे व्यय सुनिश्चित करें और एसएनए शेष राशि को कम करें तथा उसके बाद निधियां जारी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव प्रस्तुत करें। आज की स्थिति के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में राज्य से कार्यक्रम निधियां जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****